

गत 2 वर्ष में 7.2० लाख श्रमिकों को 8०4 करोड़ की सहायता दी- भजनलाल

जयपुर, 1० नवम्बर। श्रमिक वर्ग किसी भी देश या प्रदेश के विकास में विश्वकर्मा की भूमिका निभाता है। उनके कठोर परिश्रम से ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का ढ ंचा तैयार होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि श्रमिकों की सुरक्षा और उनका गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। इसी लक्ष्य के तहत, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विभिन्न श्रमिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से विगत 2 वर्षों में ही 7 लाख 2० हजार से अधिक पात्र श्रमिकों को 8०4 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। विभिन्न राज्य स्तरीय कार्यक्रमों में555 करोड़ रुपए से अधिक की राशि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से दी गयी है।

राज्य सरकार द्वारा संचालित निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा व कौशल विकास के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके तहत, कक्षा 6 से आगे की पढ़ाई के लिए 8 हजार रुपये से लेकर 25 हजार रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही, 8 वीं कक्षा से आगे अध्ययनरत मेधावी छात्र-छात्राओं को 4 हजार रुपये से लेकर 35 हजार रुपये तक की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

राज्य सरकार ने श्रमिक वर्ग के जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में उनके लिए संचालित निर्माण श्रमिक जीवन व पवित्र्य सुरक्षा योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से उन्हें लाभान्वित करने

राज्य की योजनाओं में श्रमिकों के बच्चों को 8 से 25 हजार रूपए की छात्रवृत्ति दी जाती है



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

के लिए उनके अंशदान का आंशिक व पूर्ण पुनर्भरण किया।

श्रमिकों के जीवन व सामाजिक स्तर में सुधार के लिए राज्य सरकार ने उनके पूरे परिवार को आत्मनिर्भर बनाने का प्रण लिया है। इसी उद्देश्य से उनके बच्चों को भारतीय प्रशासनिक सेवाओं

की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक लाख तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने 5० हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। विगत 2 वर्षों में इन योजनाओं में अभूतपूर्व कार्य कर श्रमिकों के जीवन के हर पड़ाव पर उनका साथ दिया जा रहा है। साथ ही

■ श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना , पीएम जीवन ज्योति योजना तथा अटल पेंशन योजना से लाभान्वित करने के लिए उनके अंशदान का आंशिक व पूर्ण पुनर्भरण किया जाता है।

आईटीआईआईएम में प्रवेश मिलने पर भी ट्यूशन फीस का पुनर्भरण सरकार द्वारा किया जाता है। श्रमिकों एवं उनके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए भी राज्य सरकार ने अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता योजना संचालित की है। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने पर 2 लाख, कांस्य पदक जीतने पर 5 लाख, रजत पदक हासिल करने पर 8 लाख और स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। विगत 2 वर्षों में इन योजनाओं में अभूतपूर्व कार्य कर श्रमिकों के जीवन के हर पड़ाव पर उनका साथ दिया जा रहा है।

सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों और कृषि संगठनों के साथ परामर्श किया

वर्ष 2026-27 के बजट की तैयारियों के संदर्भ में केन्द्रीय वित्त मंत्री विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रही हैं

नयी दिल्ली, 1० नवंबर। वित्त एवं कार्पोरेट और मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वर्ष 2०26-27 के बजट प्रस्तावों की तैयारियों सिलसिले में सोमवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों और किसान संघों तथा कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ दो अलग अलग बैठकें की।

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इन बैठकों की जानकारी देते हुए कहा, अर्थशास्त्रियों के साथ हुई पहली बैठक में वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव , सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।(सीतारमण अगले वित्त वर्ष का बजट अगले साल पहली फरवरी को

पेश कर सकती हैं। हर केंद्रीय वित्त मंत्री हर बजट की तैयारी से पहले अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करते हैं।

अगले बजट की तैयारी ऐसे समय हो रही है जबकि दुनिया भू-राजनैतिक अनिश्चितताओं से घिरी है और अमेरिका ने अगस्त से भारत के मामले में 5० प्रतिशत का भारी शुल्क लगा रखा है।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
रिकाॉर्डिंग का सावधानीपूर्वक विश्लेषण कर रहे हैं और विस्फोट के समय आसपास के क्षेत्र में सक्रिय मोबाइल फोन का डंप डेटा एकत्र किया है। अधिकारी प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज कर रहे हैं।

गाज़ा युद्ध की रिपोर्टिंग में पक्षपाती रही है। कई लोगों ने बी.बी.सी. पर “यहूदी विरोधी” रुख अपनाने के आरोप भी लगाए।
तथापि, बीबीसी के चेयरमैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इन आरोपों का कड़ा खंडन किया है। उनका कहना है कि संस्था में कोई संस्थागत पूर्वाग्रह नहीं है और उसने हमेशा अपने दर्शकों को निष्पक्ष खबरें देने की कोशिश की है।
तथापि, संस्था के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह जरूर स्वीकार किया कि “पैनोरमा” प्रसारण के बाद कार्यवाही की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई।

तथापि, पूरी घटना यह दर्शाती है कि बी.बी.सी. ने हर बार अमेरिका की नाराज़गी के आगे झुकने की प्रवृत्ति दिखाई है।
ट्रंप प्रशासन की ओर से बी.बी.सी. पर, उसकी निष्पक्षता और भरोसेमंद समाचारों का स्रोत होने पर लगाए गए गंभीर आरोपों के खिलाफ विधानसभा ने अपने बचाव में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जिस तरह यह मामला संभाला गया और जिस तबियत से संस्था पर हमले हुए उससे यह आभास होता है कि बी.बी.सी. ने वाइट हाउस में बैठे, अस्थिर स्वभाव वाले अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके समर्थकों को शांत करने का प्रयास किया है।

तहसीलदार बताए 15 दिन में, रिपोर्ट कैसे बदली

जयपुर, 1० नवंबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने फुलेरा में रिसॉर्ट के लिए जमीन आवंटन करने से जुड़े मामले में स्थानीय तहसीलदार को 24 नवंबर को पेश होने को कहा है। अदालत ने तहसीलदार से पूछा है कि एक रिपोर्ट में संबंधित भूमि को पहाड़ और नाला क्षेत्र की बताने के बाद पन्द्रह दिन में ही उसे कैसे बदल दिया गया। अदालत ने मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख राजस्व सचिव,

■ हाई कोर्ट ने फुलेरा में रिसॉर्ट के लिए भूमि रिपोर्ट पर जवाब तलब किया।

जयपुर कलेक्टर और तहसीलदार सहित अन्य से जवाब तलब किया है। वहीं, अदालत ने मामले में कलेक्टर को अपना शपथ पत्र पेश करने को भी कहा है। एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने ये आदेश लालाराम गुर्जर व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता निखिल सैनी ने अदालत को बताया कि राजईज राजस्थान के तहत फुलेरा में रिसॉर्ट निर्माण के लिए निजी पक्षकार ने राज्य सरकार से एमओयू किया था। स्थानीय तहसीलदार ने गत 17 जून को एक रिपोर्ट तैयार कर कहा कि आर्वेटित की जाने वाली भूमि पहाड़ी भूमि है और वहाँ नाला भी बहता है। ऐसे में इसे आर्वेटित नहीं किया जा सकता।

याचिका में कहा गया कि इसके कुछ दिन बाद 3० जून को तहसीलदार ने अपनी दूसरी रिपोर्ट में माना कि जमीन को आर्वेटित किया जा सकता है। वहीं तहसीलदार ने अपनी पूर्व की रिपोर्ट से पहाड़ी भूमि को लेकर कही बात को भी हटा दिया।

“ डिजिटल गिरफ्तारी ” से 3००० करोड़ की उगाही से सुप्रीम कोर्ट चिन्तित

उच्चतम न्यायालय की डबल बेंच ने मामले को सख्ती से निपटाने के संकेत दिये

■ अदालत ने कहा कि भारत के भीतर और बाहर सक्रिय परिष्कृत घोटाला नेटवर्क से जनता की रक्षा के लिये एक मजबूत तंत्र की तुरंत आवश्यकता है।

अदालत सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीएओआरए) की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों पर स्वतः संज्ञान कार्यवाही में हस्तक्षेप की माँग की गई थी।

एससीएओआरए ने अदालत से पुलिस बलों, बैंकों, साइबर सेल और वित्तीय मध्यस्थों के लिए एक राष्ट्रव्यापी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने का आग्रह किया है ताकि डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के

मामलों को समान रूप से निपटाया जा सके। पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब माँगा है और संकेत दिया है कि इस मामले पर विस्तृत विचार किया जाएगा।

खड़गे, राहुल ने दिल्ली विस्फोट पर गहरी संवेदना जताई

नयी दिल्ली, 1० नवंबर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को दिल्ली विस्फोट की घटना पर गहन संवेदना जतायी।

खरगे ने कहा , ” दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर सुनकर बेहद दुःख हुआ। शुरुआती रिपोर्टें से पता चला है कि इस घटना में कई अनमोल जानें गई हैं। इस दुःख की घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। हम चायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इस विस्फोट की शीघ्र एवं गहन जाँच सुनिश्चित करनी चाहिए, जो एक उच्च सुरक्षा और अक्सर भीड़-भाड़ वाली जगह पर हुआ है, ताकि इस चूक और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जा सके। गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा , ”दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुःख हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुःखद है। इस दुःख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी चायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूँ।”

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

एफएसएल के साथ जांच शुरू कर चुकी हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच के आदेश दे दिये गये हैं।

वहीं शाह ने सोमवार देर रात घटनास्थल का दौरा किया और वे मंगलवार सुबह गृह मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक में इस पर चर्चा करेंगे।

शाह ने कहा कि घटना किस कारण से हुई अभी यह कहना बड़ा मुश्किल है। इसकी हर पहलू से जांच करेंगे। घटनास्थल से जो नमूने मिलेंगे जब तक एनएसजी और एफएसएल इसका विश्लेषण नहीं करते इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। मगर हम हर

पता चला कि पोस्टर अदील अहमद राथर ने लगाए थे।
उसे ट्रैक कर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया।
जांच में पता चला कि राथर पिछले वर्ष अक्टूबर तक अनंतनाग के

पता चला कि पोस्टर अदील अहमद राथर ने लगाए थे।
उसे ट्रैक कर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया।
जांच में पता चला कि राथर पिछले वर्ष अक्टूबर तक अनंतनाग के

खड़गे और राहुल से गठबंधन पर बात करेंगे उद्धव

मुंबई, 1० नवंबर। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में गठबंधन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बातचीत कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक, उद्धव ठाकरे आगामी दो दिसंबर से शुरू होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले महा विकास अघाड़ी (एमवीए) और राठ ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) के बीच गठबंधन की बात कर सकते हैं। इस बीच वरिष्ठ कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने सोमवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि उनकी पार्टी बृह-मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। हालांकि यह भी कहा कि अगर समान विचारधारा वाली पार्टियों की ओर से कोई प्रस्ताव आता है, तो उस पर विचार किया जायेगा।

‘रुस परमाणु परीक्षण प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा’

मास्को, 1० नवंबर। रुस ने हाल ही में ब्यूरोस्टैनिक मिसाइल और पोसाइडन ड्रोन के परीक्षण पर चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि इनमें परमाणु विस्फोट जैसी कोई बात नहीं थी।

रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस का परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है। हमें अपने दायित्वों का पता है, लेकिन अगर अन्य देश ऐसा करते हैं तो वह परीक्षण फिर से शुरू कर देगा। पेस्कोव पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा पेंटागन को परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के लिए तैयार रहने के निर्देश देने के बाद उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। ट्रंप ने रूस और चीन पर "गुप्त" परमाणु परीक्षण करने का आरोप लगाया था, जिसे दोनों देशों ने खारिज कर दिया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टें के अनुसार, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बाद

■ रुस के प्रवक्ता ने कहा कि यदि किसी अन्य देश ने परीक्षण किया तो रुस भी परीक्षण करेगा।

में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के प्रति रूस की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, लेकिन चेतावनी दी कि अगर अमेरिका या अन्य देश परीक्षण फिर से शुरू करते हैं, तो रूस "उचित जवाबी कार्रवाई" करेगा। कुछ पश्चिमी मीडिया ने उनकी टिप्पणी को परीक्षणों की तैयारी के आदेश के रूप में गलत समझा। पेस्कोव ने रविवार को पत्रकार पावेल ज़ारुबिन के साथ प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा, "पुतिन ने बार-बार कहा है कि रूस अपने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध दायित्वों के प्रति प्रतिबद्ध है और हमारा उनका उल्लंघन करने का कोई इरादा नहीं है।"

बी.बी.सी. के सी.ई.ओ. व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
बीबीसी के “पैनोरमा” कार्यक्रम के लिए संपादित किया गया था। ट्रंप के भाषण के दो हिस्से इस तरह संपादित गए कि ऐसा लगा जैसे वह भीड़ को हिंसा के लिए उकसा रहे हों।

ट्रंप ने बाद में आरोप लगाया कि उन्होंने तो इसके विपरीत, घिरे हुए कैपिटल हिल में मौजूद बहादुर वीरों की प्रशंसा की थी। इस घटना के बाद से ही ट्रंप बीबीसी को “फेक न्यूज़” फैलाने वाला संगठन कहने लगे। यहाँ तक कि वाइट हाउस के प्रवक्ता ने भी ऐसी टिप्पणी की।

पूरा हंगामा तब सामने आया जब बीबीसी के पूर्व सलाहकार माइकल प्रेस्कॉट का एक आंतरिक जापन मीडिया में लोक हुआ। यह दस्तावेज ब्रिटेन के अख़बार “द टेलीग्राफ़” में प्रकाशित हुआ, जिसके बाद बीबीसी में तूफान मच गया। बीबीसी के महानिदेशक और समाचार प्रमुख, दोनों ने जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया।

माना जा रहा है कि यह विवाद शाब्द ज्वलद ही थम जाता, अगर यह ट्रंप के वाइट हाउस से नहीं उठा होता।

सचचाई यह थी कि पैनोरमा कार्यक्रम का प्रसारण बी.बी.सी. की आंतरिक टीम ने नहीं, बल्कि एक बाहरी टीम ने तैयार किया था। लेकिन इससे

■ इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी अभी तक, अतः दोनों मुख्य अधिकारियों ने इस प्रकरण में अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे दिया।

संस्था की निष्पक्ष और सच्ची रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। बीबीसी के चेयरमैन समीर शाह ने स्वीकार किया कि यह संगठन की गलती थी।

साथ ही, एक इतने बड़े समाचार संगठन में, जो हर दिन दुनिया भर के विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित करता है, कभी-कभी निर्णय में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन इस गलती का फायदा उठाते हुए ब्रिटेन के दक्षिणपंथी मीडिया, और उससे भी आगे अमेरिका के अतिदक्षिणपंथी मीडिया संस्थानों ने बी.बी.सी. पर “पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग” का आरोप लगाया शुरू कर दिया।

इस विवाद के संदर्भ में, दक्षिणपंथी समूहों ने बी.बी.सी. के समाचारों और कार्यक्रमों पर अन्य आरोप भी लगाए और कहा कि संस्था इजरायल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रुख रखती है और

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसेस अरावली प्रिन्टर्स , राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65०15/96, जयपुर कार्यालय: सुघर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 41०3333-34 फैक्स : ०141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386०31, 2386०32,फैक्स:०744-2386०33, उदयपुर कार्यालय: आयड मैंन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413०92, फैक्स : ०294-241०146, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 22००66०, फैक्स ०151-2527371, जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: ०2973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-2०1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 23०2०0, 23०4०0, फैक्स: ०7469-23०6०० चूरू कार्यालय : एच-15०, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 2569०6, 2569०7, फैक्स: ०1562-2569०8

